B-2

L-15

दिनांक
23-11-23

कांग्रेस की स्थापना

⇒ सेफ्टी वाल्व का सिद्धान्त :-

- 1885 में स्थापित कांग्रेस भारतीय इतिहास में न सिर्फ एक संस्था या संगठन की पहचान बनी बल्कि आजादी की लड़ाई का ही पर्याय बन गई किन्तु इस संस्था की स्थापना के साथ ही कुछ विवादों ने भी जन्म लिया जिसमें सबसे प्रचलित व लोकप्रीय विवाद "सेफ्टी वाल्व सिद्धान्त" के नाम से जाना जाता है जिसे लाला लाजपत राय ने सबसे ज्यादा प्रचारित किया।

सेफ्टी वाल्व एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी तंत्र से जुड़कर उस पर पड़ने वाले दबाव को समाप्त कर देती है।

कांग्रेस के बारे में ऐसा इसलिए कहा गया कि जन असंतोष रूपी दबाव से ब्रिटिश सत्ता को बचाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में अंग्रेजों ने जानबूझ कर कांग्रेस की स्थापना कराई अर्थात इसे सरकारी षड़यंत्र का सिद्धान्त भी कहा जा सकता है।

इस सिद्धान्त के समर्थकों के तर्क हैं—

- कांग्रेस के संस्थापक A.O ह्यूम न सिर्फ यूरोपीय थे बल्कि सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे अतः दरबार के

प्रतिनिधि के रूप में उनका झुकाव ब्रिटिश सत्ता की ओर होना स्वभाविक है।

- इस सिद्धान्त को और मजबूती तब मिली जब कांग्रेस के प्रथमअध्यक्ष रहे W.C बनर्जी ने बाद में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि "हम डफरिन के निर्देशन में काम कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस के एक अन्य अध्यक्ष रहे विलियम वेडरबर्न ने "ह्यूम की जीवनी" नामक पुस्तक में इसी तरह का उल्लेख किया।

- यदि कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों व कार्यक्रमों को आधार बनाया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहती ही नही थी, इसीलिए उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोगी जैसा व्यवहार किया।

- 1857 के महाविद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह सूचना मिलने लगी थी कि भारत में संगठित विद्रोह की भावना पनपने लगी है अतः एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य कर सके।

सेफ्टी वाल्व सिद्धान्त को ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर स्वीकारा नही जा सकता क्योंकि—

- A.O. ह्यूम एक मानवतावादी विचारक थे जो उनके लेखों व वक्तव्यों से मानव कल्याण के प्रति उनकी सोच को स्पष्ट कर देता है इसी सन्दर्भ में वे भारतीयों के अधिकारों

के प्रति संवेदनशील थे और उन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए भारतीयों को एकजुट होने का सन्देश दिया था अतः मात्र विदेशी होने के कारण ह्यूम के व्यक्तित्व को साम्राज्यी षड़यन्त्र का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

- कांग्रेस की स्थापना को किसी शून्य या निर्वात में न देखकर इसके पीछे के दीर्घकालिक इतिहास को समझना होगा, जिसकी शुरुआत 1830 के दशक से होने लगी थी —

(a) 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में स्थापित पहला संगठन माना जाता है जिसने जमींदारों के हितों की रक्षा को अपना उद्देश्य माना वस्तुतः यह एक स्वार्थी व वर्गीय संगठन था किन्तु अपनी मांगों को रखने के लिये भारत में संगठन स्थापना की नींव इसी ने रखी।

(b) 1857 के महाविद्रोह के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता अब रूढ़िवादी तत्वों से समझौता करने लगी और नवोदित शिक्षित मध्य वर्ग यह समझने लगा था कि औपनिवेशिक शासन प्रणाली भारतीय संसाधनों का शोषण कर रही है और इसी सन्दर्भ में नौरोजी ने इसे "अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया" कहा।
अतः 1870 का दशक आते-आते आद्य-राष्ट्रवाद अब राष्ट्रवाद में रूपांतरित होने लगा और पहले क्षेत्रीय संगठन जैसे बम्बई एसोसियेशन, मद्रास महाजन सभा जैसी संस्थायें स्थापित होने लगीं और अब नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में आने लगा।

(c) 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ने भारतीयों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व की मांग की शुरुआत की और 1876 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में "इंडियन एसोसिएशन" की स्थापना ने एक वृहद राष्ट्रीय मंच की परिस्थितियां निर्मित कर दीं और इसी की परिणति "अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस" के रूप में सामने आई अतः कांग्रेस की स्थापना हमारे दीर्घकालिक राष्ट्रवादी चेतना के विकास के रूप में देखी जानी चाहिए न कि इसे आयातित या आकस्मिक स्थापित संस्था के रूप में।

निष्कर्षतः सेफ्टी वाल्व सिद्धान्त कांग्रेस की स्थापना की पूर्णतः तार्किक व्याख्या नहीं कर पाता बल्कि इसे राष्ट्रवादी चेतना के विकास के रूप में समझना अधिक तार्किक होगा।

विशेष - गोखले ने इस सिद्धान्त की आलोचना के रूप में तड़ित चालक की बात की।

प्रश्न- सेफ्टी वाल्व सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं और कांग्रेस की स्थापना को यह किस सीमा तक स्पष्ट करने में सक्षम है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

उदारवाद (1885-1905)

लक्ष्य

- प्रारम्भिक नेतृत्व उदारवादी कहलाया जिसका लक्ष्य स्वशासन की प्राप्ति था और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ये भारतीय अधिकारों व हितों की रक्षा करना चाहते थे

- उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रीयता में विश्वास करते थे, उनके लिए लोकतंत्र का आदर्श मॉडल ब्रिटिश शासन प्रणाली ही था और यह नेतृत्व भारत के आधुनिकीकरण में अंग्रेजों की अनिवार्य भूमिका मानता था।

- उदारवादी नेतृत्व सामान्यत: अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चिमी मूल्यों के प्रति आकर्षण का भाव रखता था और प्रगतिशीलता के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करता था।

उग्रवाद (1905-1917)

- इनका लक्ष्य स्वराज्य को प्राप्त करना था और इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हुये स्वावलम्बन के आधार पर गैर-संवैधानिक तरीके से भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया।

- उग्रवादियों के सपनों के भारत में अंग्रेजों की कोई भूमिका नही थी, ये औपनिवेशिक शासन को प्रत्येक दृष्टि से भारत के लिए हानिकारक मानते थे। ये यथार्थवादी थे इसीलिए अंग्रेजों द्वारा किये गये अवसंरचनात्मक विकास को भी इन्होने शोषण का हिस्सा माना जैसे- रेलवे।

- उग्रवादियों ने भारत में बढ़ते पश्चिमी प्रभाव का प्रबल विरोध किया और वे "अतीत से प्रेरित होकर नये भारत का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए वे पुनर्स्थापनावादी कहलाये।

रणनीति / कार्यक्रम

- उदारवादियों ने ब्रिटिश सत्ता से सहयोग की रणनीति अपनाई और भारतीयों के अधिकारों को क्रमशः प्राप्त करने का लक्ष्य रखा और इस नेतृत्व ने संविधानवाद व कानूनवाद में विश्वास दिखाया।

- उदारवादियों ने बड़ी ही सावधानी से ऐसे कार्यक्रम तैयार किये जिस पर दीर्घकालिक आन्दोलन चलाया जा सके।

इन्होंने राजनैतिक प्रशासनिक व आर्थिक मांगों को इस तरह तैयार किया कि भारतीयों के अधिकतम हितों की पूर्ति हो सके और इन्होंने आरम्भ में सामाजिक मांगों को नहीं उठाया क्योंकि वर्ग संघर्ष की स्थिति उभरने से आन्दोलन की व्यापकता प्रभावित होती।

(**राजनैतिक मांग** – विधान सभा में भारतीयों को शामिल करना, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक कोष पर भारतीयों का नियंत्रण

प्रशासनिक मांग – ICS का भारतीयकरण, शक्ति का पृथक्करण, न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण हो

- उग्रवादियों ने स्वावलम्बन को आधार बनाते हुए गैर-संवैधानिक विधि से भी स्वराज प्राप्त करने के लिए मुख्यतः चार कार्यक्रम बनाये -

1- राष्ट्रीय शिक्षा
2- स्वदेशी
3- बहिष्कार
4- निष्क्रीय प्रतिरोध

- उग्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा मैकाले के मानसिक गुलाम बनाने की रणनीति को जवाब देना चाहा तथा भविष्य के आन्दोलनों के लिए व मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा को अनिवार्य माना।

स्वदेशी व बहिष्कार की रणनीति से न सिर्फ इन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया बल्कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आत्मिक व नैतिक बल भी प्राप्त किया।

निष्क्रीय प्रतिरोध मुख्यतः अरविन्द घोष द्वारा प्रचारित किया गया, जो इस बात का संकेतक था कि अब भारतीय

KGS IAS

आर्थिक मांगे- सूती वस्त्र पर अनुचित कर समाप्त हो, भारत में औद्योगीकरण आरम्भ हो, तथा श्रमिकों व किसानों की स्थितियों में सुधार किया जाये।) अनुचित शोषण बर्दाश्त नही करेंगे और भारतीयों की प्रतिरोध क्षमता के द्वारा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे।

योगदान / प्रभाव

- उदारवादी अपने दौर के "छात्र व शिक्षक" दोनों ही थे क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय संघर्ष की रणनीति को समझना भी था और लोगों का समझाना भी।

उदारवादियों ने औपनिवेशिक शासन की आर्थिक मीमांसा से उनके वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसी सन्दर्भ में कहा जाता है कि उदारवादियों का राजनैतिक पक्ष भले ही नरम रहा हो किन्तु उनका आर्थिक विश्लेषण किसी क्रांति से कम नही था।

उदारवादियों ने सिविल सर्विस के भारतीयकरण की मांग से दोहरा कार्य किया- धन की निकासी पर रोक तथा भारतीयों के शोषण में कमी।

- आधुनिक इतिहास में उग्रवादियों को ही यह श्रेय जाता है कि राष्ट्रीय संघर्ष में जन-आन्दोलन की शुरुआत की। स्मरणीय है कि उदारवादियों ने अपने आन्दोलन को शहरी व शिक्षित वर्ग तक सीमित रखा था जिससे आम जनता राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर होने लगी थी अत: आन्दोलन से जनता के जुड़ाव के लिए उग्रवादियों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया इसी सन्दर्भ में तिलक ने गणेश व शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की।